(ग) "पोल" लगाने पर कितनी लागत आयी और उनको हटा कर दूसरी जगह लगाने पर कितनी लागत आई; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं । रज्जुमार्ग, लदे कोयले की भारी मात्रा की घनत्वता के लिए निरूपित सुविधा के अनुपयुक्त हो जाने तथा बकेट पद्धति के समस्यामूलक बन जाने के कारण अप्रचालनीय हो गया है । रज्जू-मार्ग के ठप्प हो जाने के दौरान भारतीय रेलवे कोयले की ढुलाई कर रहा है ।

(ख) कुटेश्वर खानों में रज्जूमार्ग के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव था जो खर्चीला पाया गया और इसलिए उसे त्याग दिया गया । अतः रज्जुमार्ग को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । वास्तव में इसके पुनः प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए इसमें संशोधन का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) उपरोक्त "क" और "ख" भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भिलाई इस्पात संयंत्र से स्क्रैप उठाने का ठेका श्री अरविन्द जायसवाल को दिया जाना

3423. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर इंजीनियरिंग वर्क्स, नागपुर के एक मालिक श्री अरविन्द जायसवाल को भिलाई इस्पात संयंत्र का 90 प्रतिशत स्क्रैप उठाने का ठेका दिया गया है जिसके द्वारा उसने करोड़ों रुपये कमाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियों ने कुछ समय पहले श्री जायसवाल को दिवालिया घोषित किया था; और

(ग) यदि हां, तो भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधक वर्ग ने उसे स्क्रैप उठाने का ठेका किन आधारों पर दिया ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने ने मेसर्स नागपुर इंजीनियरिंग वर्क्स के साथ न तो कोई अनुबन्ध किया है और न ही उसे स्क्रैप माल की बिक्री की है ।

तथापि, वर्ष 1989-90 तथा चालू वर्ष के दौरान मेसर्स नागपुर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को क्रमशः 150 मी. टन तथा 600 मी. टन स्क्रैप की कुछ मात्रा की बिक्री की गयी है । श्री अरविन्द जायसवाल मेसर्स नागपुर इंजीनियरिंग कम्पनी लि., नागपुर के प्रबन्ध-निदेशक हैं । धमन भट्ठी धातु-मल ढेर से लौह स्क्रैप की पुनर्प्राप्ति, स्थानान्तरण तथा ढुलाई से सम्बन्धित कार्यों का ठेका अप्रैल, 1990 से खुली निविदा के अन्तर्गत उच्चतम बोली की स्वीकृति के आधार पर मेसर्स कारपोरेट इस्पात अलायस (प्रा.) लि., को दिया गया है । श्री अरविन्द जायसवाल मेसर्स कारपोरेट इस्पात अलायस (प्रा.) लि. के अंशधारी हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Programme for Mineral Excavation in Madhya Pradesh

3424. SHRI AJIT P. K. JOGI :
KUMARI ALIA :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 371 given in the Rajya Sabha on the 28th December, 1989 and state :

(a) what is the programme for mineral excavation during 1990-91 under Central and State sectors separately in Madhya Pradesh;

(b) whether assistance from international agencies has been sought/availed of for this purpose; and

(c) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Export of High Value Added Products

3425. SHRI S. MADHAVAN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what steps Government have taken to phase out the export of raw materials of low value added products to promote the export of high value added products;

(b) what steps have been taken for the phasing out the export of finished leather to promote export of leather products; and

(c) what steps have been taken to phase out the export of raw and semi-processed granite ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU) : (a) The Export Import Policy is oriented towards achieving higher value addition on exports. Replenishment rates are dependent on value addition. The scheme of 100% Export Oriented Units and Export Processing Zones are founded on the concept of value addition.

(b) A Group was set up by the Government to consider phasing out of export of finished leather so as to promote exports of value added leather products. The Group has recommended regulation of export of finished leather over a period of time.

(c) There is no ban on export of granite blocks. However, the respective State Governments have been generally adopting policies that discourage export of raw and unfinished granite. Under the scheme of 100% Export Oriented Units, approval for schemes in the granite sector are accorded on the basis of optimum value addition and processing.

Clearance of Peddagedda Reservoir Scheme

3426. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Peddagedda reservoir scheme (medium irrigation) in Vizianagram district of Andhra Pradesh has since been cleared by the Central Water Commission;

(b) if so, what are the details therefor; and

(c) if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER FOR TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV) :

(a) to (c) The project has been returned to the State Government in March, 1990, to comply with observations of Central Water Commission, regarding carryover storage, reservoir competency, benefit cost ratio and clearance for submergence of forest land. The State Government has to come up with a modified report.

Merger of the cadre of Investigator with the cadre of Technical Assistant in the Office of Development Commissioner (Handicrafts)

3427. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cadre of Investigator in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) has been disturbed with its merger with the cadre of Technical Assistant, defying all norms;

(b) whether it is also a fact that the merger of cadres will adversely affect the promotion avenues of existing Investigators who in fact have not got any promotion for the last 10 years; and

(c) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV) : (a) to (c) There has been no merger as such. However, the Technical Assistants in the Metal Scheme have been made eligible